



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 880]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2005/श्रावण 31, 1927

No. 880]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2005/SRAVANA 31, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2005

का.आ. 1168(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 150 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, पोर्ट-ब्लेयर में मुख्यालय से युक्त एक अधिकरण गठित किया और उक्त अधिकरण में श्री जनक दीगल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र: 1985) को दिनांक 2 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 502 (असाधारण) द्वारा, वर्ष, 2004 की रिट याचिका संख्या 120 से उद्भूत, अन्तर-द्वीप-नाविक संघ और अन्य के आवेदन में उठाया गया विवाद निबटाने हेतु उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर उपर्युक्त अधिकरण का अधिनियम, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए नियुक्त किया।

अबकि श्री जनक दीगल के अनुरोध पर उपर्युक्त अधिकरण द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय दो बार अर्थात् एक बार दिनांक 4 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना द्वारा, 30 अप्रैल, 2005 तक और उसके बाद दिनांक 26-5-2005 की अधिसूचना द्वारा, 15-6-2005 तक बढ़ा दिया गया।

जबकि श्री जनक दीगल ने अपने दिनांक 12 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा यह बताया है कि (i) इस मामले में एकमात्र प्रतिवादी, निदेशक, पोत परिवहन सेवा, अण्डमान और निकोबार प्रशासन, उपर्युक्त अधिकरण से सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस मंत्रालय के दिनांक 10-6-2005 के पत्र द्वारा निदेश जारी कर दिए जाने के बाद अब, उनके (निदेशक, पोत परिवहन सेवा, अण्डमान और निकोबार प्रशासन) द्वारा सहयोग किए जाने की उम्मीद है तथा (ii) अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारियों के, उपर्युक्त द्वीप समूह में खारीफ की फसल की जुताई के मुख्य समय, जुलाई-अगस्त, 2005 के दौरान सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि से संबंधित बहाली और पुनःस्थापन के कार्यों में व्यस्त होने के कारण, उपर्युक्त अधिकारी (श्री दीगल) द्वारा सुनवाई की कार्यवाही संचालित कर पाना और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं होगा। अतः उन्होंने उपर्युक्त अधिकरण द्वारा उपर्युक्त विवाद के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय 30-9-2005 तक बढ़ा देने का अनुरोध किया है।

श्री जनक दीगल के उपर्युक्त अनुरोध पर विचार करके, केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त अधिकरण द्वारा उपर्युक्त विवाद के बारे में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु उसका कार्य-काल, एतद्वारा 30-9-2005 तक और बढ़ा देने का निर्णय करती है।

[फ. सं. एस एस-14017/11/2004-एस वाई-II]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd August, 2005

S.O. 1168(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 constituted a Tribunal with Headquarters at Port Blair appointing Shri Janak Digal, IAS (AGMUT: 1985) to the said Tribunal with the direction to submit the Award to the Tribunal to the Central Government within one month from the date of publication of the notification, for settling the dispute raised in the application of Inter-Island Seamen Union and another, arising from Writ Petition No. 120 of 2004, *vide* notification No. S.O. 502(E) dated 2nd February, 2005.

Whereas at the request of Shri Janak Digal the time for submission of the report by the Tribunal was extended twice i.e. once upto 30-4-2005 *vide* notification dated 4th April, 2005 and thereafter up to 15-6-2005 *vide* notification dated 26-5-2005.

Whereas Shri Janak digal *vide* his letter dated 12th July, 2005 has stated that (i) the Director of Shipping Services, A&N Admn. who is one of the defendant in the case, did not cooperate with the tribunal and that now after the issue of directions by the Ministry *vide* letter dated 10-6-2005 he is expected to cooperate and (ii) the officers of Andaman and Nicobar Administration would be busy in agricultural rehabilitation work in Tsunami affected areas during July-August, 2005, which is main cultivation period for Khariff crop in the Islands, it would not be possible for him to conduct hearings and submit report. Therefore, he has sought time for submission of report by the Tribunal up to 30-9-2005.

Having considered the request of Shri Janak Digal, the Central Government hereby further decides to extend the tenure of Tribunal up to 30-9-2005 for submission of the report to the Central Government.

[F. No. SS-14017/11/2004-SY-II]

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.